की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना के अतर्गत उपलब्ध हुए धान और गेहू की बीजो, उर्वरको, सिचाई और मजदूरी की प्रति हैक्टार लागत के अनुमान सभा पटल पर रखे गए विवरण 1 मे दिए गए हैं [ग्रथालय मे रखा गया देखिए सख्या एल टी 8977/75] जहा तक गन्ने का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र प जाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यो में 1973–74 की लागत के आकडे एकत्र किए गए हैं । इस समय जाच कर इन्हे सकलित किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र म 1974–75 की लागत के आकडे एकत्र किए जा रहे हैं ।

(ख) 1970–71 से 1974–75 तक के खरीफ । रबी मौसमो के लिए धान, चावल और गेहू के लिए निर्धारित किए गए वसूली मू य सभा पटल पर रखे गए विवरण 2 मे दिए गए ह [ग्रथालय मे रखा गया । देखिए सख्या एल टी] जहा तक गन्ने का सबध है, इस प्रकार का कोई वसूली मू य निर्धारित नही किया गया है । तथापि चीनी के कारखानो द्वारा अदा किया जाने वाला एक साविधिक न्यूनतम मूल्य वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है । इसका ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण 3 मे दिया गया है । [ग्रथालय म रखा गया । देखिए सख्या एल टी]

(ग) न्यूनतम । वसूली मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशो के आधार पर और राज्य सरकारो की सलाह से निर्धारित किए जाते हैं । ऐसा करते समय सभी सबधित पहलुओ पर विचार किया जाता है जिसमे किसान को लाभप्रद मू य देने की आवश्यकता भी शामिल है । इसके अलावा गन्ने के मामले मे चीनी पर आशिक नियत्रण की वर्तमान नीति के अतर्गत चीनी के कारखानो से यह आशा की जाती है कि वे चीनी की खुले बाजार म बिक्री के कोटे से मिलने वाली अतिरिक्त राशि म से ऊचे मूल्य अदा करे और वस्तुत कई कारखाने अदा भी करते हैं । 1974–75 के मौसम से कारखाने के लिए साविधिक रुप से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह उसे मिलने वाली अधिक राशि का कम से कम 50 प्रतिशत गन्ना उत्पादको को गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के तौर पर दे ।

दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों को राशन की दुकान आवंटित करना

870. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या कृषि और सिचाई मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या रोजगार देने के मामले मे अन्य लोगो की तुलना मे भूतपूर्व सैनिको को प्राथमिकता देने की सरकार की कोई नीति है ,

(ख) यदि हा तो गत तीन वर्षों मे ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिको को दिल्ली मे राशन की दुकाने दी गई हैं और क्षेत्र निवासियो के सिफारिश करने पर ऐसे कितने आवेदन पत्र रद्द किए गए , और

(ग) क्या राशन की दुकानो के लिए भूतपूर्व सैनिको के आवेदनपत्र विचाराधीन हैं और यदि हा, तो इनका कब तक निर्णय कर लिया जायएगा ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार ने भूतपूर्व सैनिको के लिए श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदो/सेवाओ मे क्रमश रिक्तियो का 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत तक पद आरक्षित किए हैं । ये पद सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने हैं ।

(ङ) और (च) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को 6 राशन की दुकानें दी गई थीं और वे अस्वीकृत अर्जियों का कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं। राशन की दुकान के लिए भूतपूर्व सैनिकों की कुछ अर्जियां दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन हैं और यथासमय इन अर्जियों पर निर्णय लिया जाएगा।

Famine conditions in Jhumia Belt of Tripura and Central aid therefor

871. SHRI DASARATHA DEB: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that the entire Jhumia belt, particularly in upper portions of Kailasaher, Kamalpur, and Khowai Sub-divisions of the State of Tripura have now been under terrific famine;

(b) if so, steps being taken at present to protect, the affected Jhumia; and

(c) whether Government propose to provide a monthly cash dole to each of the affected tribal family, as is being provided to the refugees from Bangladesh even to-day?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): (a) to (c). The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Central Assistance to States for implementation of UGC Pay Scales for Colleges/University Teachers

872. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government of India's offer of Central assistance to the State Governments for implementing the University Grants Commission pay scales for college and University teachers has been reiterated; and

(b) if so, the reaction of the State Government's thereon?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): (a) Yes, Sir.

(b) Government of Uttar Pradesh have issued orders for implementatitn of the revised scales while Government of Bihar have accepted them in principle. Government of Kerala have proposed revised scales of pay, which are substantially different from those recommended by the University Grants Commission. Other States are examining the financial and other implications of the scheme.

Urban Property Ceiling Bill

873. SHRI D. P. JADEJA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government are considering to introduce an Urban Property Ceiling Bill in Parliament during the current Budget Session; and

(b) if so, the aims and objects of the Bill?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) and (b). The matter is under active consideration. Efforts are being made to introduce the Bill in the Parliament at an early date.

Enquiry into the utilisation of credit given by Gujarat State Land Development Bank

874. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether an enquiry into the utilisation of credit given by the